

[Shri M. C. Daga]

to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion was adopted.

12.57 hrs.

RULES COMMITTEE

SIXTH REPORT

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I beg to move-

"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

MR. SPEAKER: This question is:

"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

The motion was adopted.

12.57-1/2 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED DISSATISFACTION AMONGST UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS OF MADHYA PRADESH

ड० लक्ष्मी नारायण शिखे (मंडलर) : यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अनेक राज्यों ने, जिनमें महाराष्ट्र और हरयाणा भी सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के नये वेतन-मानों को लागू कर दिया है तथा अन्यथा मांगों को भी स्वीकार कर लिया है। गुजरात राज्य ने उन शिफारिशों का तासिद्धान्ततः स्वीकार किया है लेकिन अभी तक उनका अमल में नहीं लाये हैं। किन्तु मध्य प्रदेश द्वारा यू० जी० सी० के वेतनमानों के स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट करने से मध्यप्रदेश में स्थिति भयकरतम होती जा रही है। वहाँ पर शिक्षकों ने हड़ताल कर दी है और परीक्षाका का बहिष्कार कर दिया है, परंछाएँ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है जिसके कारण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अग्रघ रमय होने जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा उक्त शिक्षकों के साथ जिग प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वह अत्यन्त खेदजनक है। व्याप। गतिर घ से इंजीनियरिंग और मैडिकल में जाने वाले विद्यार्थी, नीचे की परीक्षाएँ न होने के कारण आगे जाने में असमर्थ रहेंगे। मामला अत्यधिक गंभीर है अतः केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने भी इस बारे में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है तथा समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया है। इसलिये केन्द्रीय सरकार इस मामले

में हस्तक्षेप कर के इस समस्या का तुरन्त समाधान करे, वरना स्थिति और भी भयंकर हो सकती है।

मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा मंत्री महोदय श्री नुरुल हुसन इस बारे में व्यक्तव्य देने की कृपा करेंगे। साथ ही मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं वे सभी राज्यों में समान रूप से लागू हों। मध्य प्रदेश राज्य इस बारे में जो प्रस्तावता बरत रहा है उसको दूर करना चाहिये ताकि शिक्षकों में केंद्र हस्तांतरण दूर हो सके तथा विद्यार्थियों के भविष्य पर भी विचार न भ्रंश न पड़े।

THE MINISTER OF FINANCE
(Shri C Subramaniam) I beg to move

(Interruptions)

MR SPEAKER It is impossible for this House to continue. It is very difficult to carry on the business.

(Interruptions)

13.00 hrs

MR SPEAKER This will not go on record.

आज लंच ब्रावर रखा हुआ है। क्या आप लंच ब्रावर चाहते हैं? जब हम लागू इतनी देर तक बिना लंच ब्रावर के काम करते रहे हैं, तो अब तीन चार दिन के लिए लंच ब्रावर रख कर क्या रना है?

We have a short time. I think we can continue to sit during lunch hour also. I put it to you that we continue to sit.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): We want lunch hour. This is the last week. For the whole of the budget session, we have not had any proper lunch.

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मदसौर)

अध्यक्ष महोदय, यह तय किया गया था कि 5 मई तक—जब तक फिनांस बिल पास न हो जाये, तब तक—लंच ब्रावर नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: अगर हम इन चार दिनों में लंच ब्रावर न रखें, तो हाउस को तीन चार घंटे और मिल जायेंगे।

क्या आप को लंच ब्रावर चाहिए या नहीं?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर लंच ब्रावर नहीं होगा।

श्री रामाचतार शास्त्री (पटना)

अध्यक्ष महोदय, क्या लंच ब्रावर नहीं होगा?

SHRI P. G. MAVALANKAR We want lunch hour and lunch, both.

MR SPEAKER I have seen the position. We are in a very tight position. That is why I put it to you that we continue as before. We will have the lunch hour on the last day.

13.02 hrs.

COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF FINANCE
(SHRI C SUBRAMANIAM) I beg to move *

"That the Bill to amend the Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Act, 1974 be taken into consideration."